खनन और पर्यटन क्षेत्र राजस्थान के विकास के प्रमुख इंजन-भजनलाल

मुख्यमंत्री ने राइज़िंग राजस्थान समिट के तहत हुए विशेष समझौतों की समीक्षा बैठक ली

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश दिये कि दिसम्बर माह में होने वाले राइज़िंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले खनन, पेट्रोकैमिकल और पर्यटन को लेकर प्री-समिट का आयोजन किया जाये।

जयपुर, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, खनिज सम्पदा, ऊर्जा क्षमता और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण वैश्विक पटल पर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए। इनके धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में बुनियादी ढ़ांचे का विकास होने के साथ ही वृहद् स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए निवेश समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमओयू से संबंधित भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों में भी तेजी लाते हुए, सभी एमओयू को समयबद्ध रूप से धरातल पर मूर्तरूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों द्वारा चाही गई लोकेशन पर जमीन उपलब्ध ना होने की स्थिति में उन्हें आस-पास के क्षेत्र में वैकल्पिक जमीन दिखाई जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि ऐसे एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि निवेशकों से लगातार संपर्क में रहते हुए समय-समय पर कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक भी करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन और पर्यटन क्षेत्र राजस्थान के विकास का इंजन है। हमें इन क्षेत्रों में प्रगति की और अधिक संभावनाओं को तलाशना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिसम्बर माह में होने वाली राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले खनन, पेट्रोकेमिकल और पर्यटन को लेकर प्री-समिटों का आयोजन किया जाए। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में जमीन में मौजूद खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वे करवाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन सैक्टर में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी धरोहर हैं और उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है।

बैठक में राजधानी जयपुर में दिसम्बर माह में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025 के आयोजन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कॉन्क्लेव में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान हुए एमओयू की क्रियान्विति से प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य में आए बदलावों के बारे में निवेशकों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

मंगलवार को भी ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 12 अगस्त। लोकसभा में लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को भी जबरदस्त हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने हंगामे के बीच खान और खनन संशोधन विधेयक पारित करवा दिया, लेकिन आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पकड़ाए गये कागज को फाड़कर हंगामा कर रहे सदस्यों ने पीठ की तरफ कागज फेंक कर सदन के अध्यक्ष का अपमान किया है। उन्होंने गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप सदन की गरिमा गिरा रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। सुबह से विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन को तीन बार स्थगित किया गया था और चौथी बार उन्होंने भारी हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जल्द

नई दिल्ली, 12 अगस्त। अगले महीने की शुरुआत से भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस की शुरुआत हो सकती है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते में काफी कड़वाहट बढ़ गई थी। करीब पांच साल बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में फिर से गरमाहट बढ़ रही है। भारत सरकार ने कहा है कि एअर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों से कहा है कि चीन के लिए तुरंत उड़ाने शुरू करने के लिए तैयार रहें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की बैठक ली।

जयपुर में पहली बार आर्मी-डे परेड़ का आयोजन होगा

मुख्यमंत्री ने सेना एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ परेड की तैयारियों पर बैठक की

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को जयपुर में आयोजित होने वाले समारोह के लिए परेड के स्थान का चयन करते समय अनुमानित दर्शक क्षमता का विशेष ध्यान रखें। साथ ही स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं, पर्यटकों व आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें।

जयपुर, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष 15 जनवरी को होने वाली आर्मी-डे परेड का आयोजन इस बार जयपुर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आर्मी-डे परेड का आयोजन भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा, जिससे युवाओं में देश भक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो सके तथा दुनिया में बदलते भारत की उभरती तस्वीर नज़र आए। शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेना के इसी शौर्य को सम्मान देने के लिए आर्मी-डे परेड के इस आयोजन को और भव्य बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्मी-डे परेड में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं तथा पर्यटकों सहित, आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, परेड स्थल का चयन करते समय अनुमानित दर्शक क्षमता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिला कलक्टर जयपुर को आयोजन स्थल का नक्शा बनाते हुए पूरा रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम में दर्शकों को राजस्थान की अद्भुत संस्कृति की झलक भी दिखनी चाहिए।

भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह ने बताया कि आर्मी-डे परेड को आम लोगों तक पहुंचाने तथा युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग दिवसों पर रक्तदान शिविर, ऑनर रन, साइकिल रैली, नो यॉर आर्मी जैसी सेना दिवस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड कार्यक्रम के दिन परेड संरचना के तहत पैदल सैनिक दस्ते, टैंक, तोप, मिसाइल, भारतीय सेना बैण्ड, मोटर साइकिल शो तथा विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के युद्ध कौशल और सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के लिए शौर्य संध्या का भी भव्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा।

बैठक में मेजर जनरल अमर रामदासानी ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सेना दिवस परेड की तैयारियों से सम्बन्धित जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित, भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जस्टिस वर्मा पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी वी आचार्य को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति से जांच रिपोर्ट मिलने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। उन्होंने समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा से पहले कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा को उनके कदाचार के लिए उनको हटाने का प्रस्ताव मिला था। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल के समय से संबंधित शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया गया। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है।

पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की पानी -गैस आपूर्ति रोकी

■ राजनयिकों को खुले बाजार से महंगे दामों में पानी व गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है।

इस्लामाबाद, 12 अगस्त। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की नई करतूत सामने आई है। उसने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों की पानी और गैस जैसी बुनियादी जरूरतों तक पर रोक लगाई जा रही है।

पाकिस्तान के स्थानीय विक्रेता पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर तक की सप्लाई करने में हिचकिचा रहे हैं यहां तक कि उच्चायोग के अधिकारियों-कर्मचारियों के घर अखबार देने से भी मना कर दिया है। पाकिस्तान की ये हरकत वियना कन्वेंशन का घोर उल्लंघन है,जो दूतावासों के सुचारू संचालन और उनके कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (एसएनजीपीएल) पाइपलाइन गैस की सप्लाई करती है। लेकिन, इसकी आपूर्ति को जानबूझकर रोक दिया गया है। स्थानीय एलपीजी सिलेंडर बेचने वालों को भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने धमकी दी है कि वे भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को इसे न बेचें। इस कारण राजनयिकों और उनके परिवारों को खुले बाजार से गैस सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं।

क्या अमित शाह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि संजय बालयान पीछे चल रहे हैं। गौरतलब है कि संजय बालयान को अमित शाह का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने ही उन्हें उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था। इस हाई-प्रोफाइल चुनाव में वोटों की गिनती की शुरुआत से ही रूडी आगे चल रहे हैं, हालांकि शुरुआती बढ़त बहुत मामूली थी। अब यह अंतर बढ़ता जा रहा है।

इज़रायल के राजदूत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिणाम है, जिनमें वे नागरिकों के पीछे छिपते हैं, उन लोगों पर गोली चलाते हैं, जो सहायता लेने या बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, और रॉकेट दागते हैं।"

उन्होंने आगे कहा : इज़रायल ने ग़ाज़ा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई, जबकि हमास उसे जब्त करने की कोशिश करता है, जिससे भूख की स्थिति पैदा होती है। ग़ाज़ा की आबादी पिछले 50 वर्षों में 450 प्रतिशत बढ़ी है वहाँ कोई नरसंहार नहीं हो रहा। हमास के आँकड़ों पर विश्वास न करें।

प्रियंका गांधी ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शर्म की बात है कि जब इज़रायल फिलिस्तीन के लोगों पर यह विनाश ढा रहा है, तब भारत सरकार चुप है। हालांकि कांग्रेस आमतौर पर फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाती रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर खुलकर बोला है। उन्होंने ग़ाज़ा में हमलों को बर्बर और नरसंहार जैसा बताया है और इज़रायल पर युद्ध रोकने का दबाव डालने की मांग की है।

मंगलवार सुबह एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि इज़रायली राज्य नरसंहार कर रहा है और 60,000 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है, जिनमें 18,430 बच्चे हैं। इसने सैकड़ों को भूख से मार दिया है, जिनमें अनेक बच्चे शामिल हैं, और अब लाखों को भुखमरी की धमकी दे रहा है। चुप्पी और निष्क्रियता के माध्यम से इन अपराधों को सहन करना स्वयं एक अपराध है।

पिछले साल दिसंबर में प्रियंका गांधी संसद में 'पैलेस्टाइन' लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची थीं, जिसमें फिलिस्तीनी प्रतीकों के रूप में तरबूज भी बना हुआ था - जो फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। तब भाजपा ने उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। पिछले साल जून में उन्होंने इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ग़ाज़ा में कथित नरसंहारात्मक कार्रवाई के लिए तीखा प्रहार किया था और मोदी सरकार की संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर मतदान से अनुपस्थित रहने की आलोचना की थी। एक पूर्व वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने राष्ट्रदूत से, नाम न बताने की शर्त पर कहा, राजनयिकों को आमतौर पर मेज़बान देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इज़रायली राजदूत ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। लगता है उन्हें विश्वास है कि केन्द्र सरकार उनके प्रियंका गांधी से टकराने पर आपत्ति नहीं जताएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजनयिकों को तटस्थ रहते हुए अपने देश के हितों को आगे बढ़ाना चाहिए।

■ बहरहाल, राजदूतों का किसी मेजबान देश की राजनीति व राजनीतिज्ञों पर शाब्दिक आक्रमण करना, किसी भी सुसंस्कारित समाज व देश में स्वीकार्य नहीं होता है।

'चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मानना सही कदम '

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर बहस के दौरान टिप्पणी की

■ बुधवार को पुनः इस मामले की सुनवाई होगी।

नयी दिल्ली, 12 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बिहार की मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण विवाद मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग का आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं मानना सही है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस दलील से भी सहमत नहीं थी कि बिहार के लोगों के पास विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग की ओर से प्रमाण के रूप में मांगे गए अधिकांश दस्तावेज नहीं थे।

शीर्ष अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से विस्तार पूर्वक दलीलें पेश की गईं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण ने विस्तार पूर्वक दलीलें पेश कीं।

याचिकाकर्ताओं में शामिल स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने ग्राफिक्स के जरिए खुद ही अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलीलें दीं।

अदालत के समक्ष चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वजह यह कि उनका या उनके माता-पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद थे।

पीठ ने आयोग की ओर से पेश इन दलीलों पर याचिकाकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल सांसद नेता मनोज झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल से पूछा, अगर 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने विशेष निरीक्षण का जवाब दिया है, तो यह आंकड़ा एक करोड़ मतदाताओं के लापता या उनके मताधिकार से वंचित होने की दलील खारिज कर देता है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि चुनाव आयोग के 24 जून के विशेष पुनरीक्षण कराने के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इससे एक करोड़ मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएँगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने इस दलील दी कि निवासियों के पास आधार, राशन और वोटर कार्ड होने के बावजूद अधिकारियों ने उनके दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सिब्बल ने कहा कि लोगों को अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज खोजने में कठिनाई हो रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने की समय-सीमा के साथ-साथ उन 65 लाख मतदाताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाया, जिन्हें मृत या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत घोषित कर दिया गया है।

स्वराज इंडिया के नेता यादव ने चुनाव आयोग पेश आंकड़ों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 7.9 करोड़ मतदाताओं के बजाय कुल वयस्क आबादी 8.18 करोड़ थी और पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को हटाना था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया जिसका नाम जोड़ा गया हो। शीर्ष अदालत में इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी।

'' भारत सरकार ने हमारे अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ मिलीभगत शामिल थी, जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी भी थे। साथ ही, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के साथ भी बैठकें हुईं, ताकि बिजली बिक्री समझौते (पावर सेल्स एग्रीमेनट्स) किए जा सकें।

अडानी समूह और रेड्डी ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है।

एसईसी ने कहा है कि वह "भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रखेगा और हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत प्रतिवादियों को समन की सेवा के प्रयास जारी रखेगा।"

ट्रम्प ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, क्योंकि सामान्यतः घरेलू अपराधों से निपटने का काम नगर पुलिस का होता है।

हालाँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ट्रंप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने अन्य प्रमुख शहरों में दंगों और विरोध प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए पहले भी सेना तैनात की थी। उन्होंने यह कदम लॉस एंजिल्स में उठाया था और तब से लगातार ऐसे कदमों की धमकी देते रहे हैं।

सम्भवतः शक्ति और वैधता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से, ट्रंप ने इसकी घोषणा करते समय अपने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को अपने पीछे खड़ा किया और दूसरी ओर उनके अटॉर्नी जनरल और खुफिया प्रमुख काश पटेल खड़े हुए थे।

राजधानी की सड़कों पर स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जो लोकतंत्र के तथाकथित गढ़ में एक तानाशाही राज्य के उभरने की चेतावनी दे रहे हैं। भारत के बाद, अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसका अधिनायकवाद की ओर झुकाव लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

विशेष रूप से, ट्रंप ने यह कदम इस पृष्ठभूमि में उठाया है, जब वे अलास्का में रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन से तीन साल पुराने यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए बैठक करने जा रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने पुतिन से मुलाकात के दौरान, वॉशिंगटन के आपराधिक परिदृश्य, और बेघरों के शिविर बन चुके वॉशिंगटन के गंदगी से भरे पार्कों का ज़िक्र करते हुए खेद जताया था।

मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह बात हतप्रभ कर देने वाली है कि ऐसा कुछ अमेरिका में हो सकता है। प्रदर्शनकारी "फ्री वॉशिंगटन" जैसे नारों वाले पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वरिष्ठ राजनेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि लॉस एंजिल्स तानाशाहीपूर्ण कदम उठाने के मामले में एक "टैस्ट केस" था, तो वॉशिंगटन पर यह सैन्य नियंत्रण एक कदम और आगे बढ़ गया है।

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही तानाशाही और असहिष्णुता की दिशा में आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने ओबामा शासन के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी की धमकी तक दी है। ये सारे कदम उन सरकारों के कदमों से मिलते-जुलते हैं, जो धीरे-धीरे पूर्ण रूप से तानाशाह सरकारों के रूप में तब्दील हो जाती हैं।

जमवा रामगढ़ में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हुआ

कौतूहलवश उमड़ी लोगों की भारी भीड़ के कारण नैटवर्क ठप्प हुआ तो ड्रोन उड ही नहीं पाया

■ बाद में मौके से लोगों को हटाने के बाद कंपनी ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल के सामने 400 मीटर ऊंचाई तक ड्रोन उडाकर डेमो दिया।

■ दावा किया जा रहा है कि, आगामी 7 से 10 दिन में ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद "क्लाउड सीडिंग" के जरिए बारिश करवाई जायेगी।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 12 अगस्त। जमवा रामगढ़ बांध के क्षेत्र में मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। बादल काफी ऊपर थे, इसलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हो पायी। कृत्रिम बारिश को देखने के लिए कौतूहलवश भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिस कारण नैटवर्क ठप्प हो गया। जी.पी.एस. सिग्नल लॉस होने के कारण ड्रोन ऑटो लैंडिंग मोड में जा पहुंचा और पुन: लैंड हो गया। काफी देर बाद पुलिस ने लोगों को मौके से हटाया और भीड़ कम हुई तो कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल के सामने ड्रोन द्वारा 400 फीट की हाइट तक सफल डेमो दिया गया।

कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनी जेन एक्स एआई के डायरेक्टर अजिंक्या धूमबाड़े ने कहा कि आज 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर डेमो किया गया। आगामी 7 से 10 दिन में ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। फिर हम ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे।

बताया जा रहा है कि जब पहली बार ड्रोन के पंखे चलाए गए, तब वह जमीन पर ही रुक गया। दूसरे प्रयास में कुछ ही ऊंचाई पर उड़ने के बाद ड्रोन बांध के नीचे जमीन पर झाड़ियों के बीच अटक गया। इसके बाद नीचे मौजूद लोग ड्रोन के पास पहुंचकर उसका वीडियो बनाने लगे। इस दौरान पुलिस से भीड़ की झड़प भी हो गई। बमुश्किल समझाकर मामला शांत कराया गया।

उधर, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया 'एक्स" पर लिखा है "डेमो ड्रोन को सफलता पूर्वक 400 फीट तक उड़ाया गया। आगामी 30 दिनों के अन्दर इस तकनीक के माध्यम से रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी।"

ज्ञात रहे कि अमेरिका और बेंगलुरु की कंपनी जेन.एक्स.एआई कृषि विभाग के साथ मिलकर यह प्रयोग करने का प्रयास कर रही है। इस प्रयोग के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के सभी विभागों से मंजूरी मिल चुकी है। कृषि विभाग, मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने जुलाई में ही मंजूरी दे दी थी। वैज्ञानिकों की टीम पिछले कई दिनों से जयपुर में है। वे लगातार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रहे हैं। अब तक देश में प्लेन से क्लाउड सीडिंग की जाती रही है। ड्रोन से छोटे इलाके के सीमित दायरे में होने वाला यह पहला प्रयोग है।

डॉ. किरोडीलाल मीणा ने कहा कि इस क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना, जल संकट को कम करना और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बहाल करना है। यह एक अनुसंधान एवं विकास आधारित पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें आधुनिक ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और एआई का उपयोग कर वर्षा को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जायेगा।

भारत में पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग की जा रही है। इसमें 'हाइड्रो ट्रेस' नामक एआई पावर्ड प्लेट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम डेटा, सेटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क की मदद से सही समय और सही बादलों को टारगेट करता है। यह 30 दिनों तक चलने वाला पायलट मिशन है।

उन्होंने बताया कि ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग में ड्रोन को बादलों के पास भेजा जाता है, जहां यह सोडियम क्लोराइड या अन्य सुरक्षित सीडिंग ऐजेंट्स छोड़ता है। इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश होती है। यह मिशन 12 अगस्त से शुरु होकर लगभग 30 दिनों तक चलेगा। शुरुआती प्रभाव हमें तुरंत बारिश के रूप में दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जल स्तर, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन पर पड़ेगा।

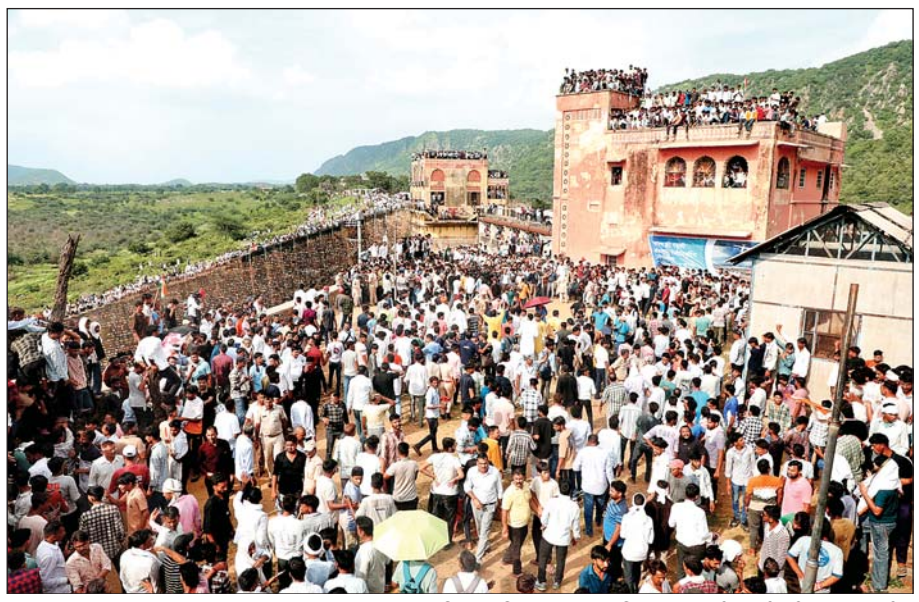

जयपुर के जमवा रामगढ़ में मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के कारण ड्रोन का नैटवर्क ठप्प हो गया जिससे ड्रोन उड़ नहीं पाया। बाद में कंपनी ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल के सामने 400 मीटर ऊंचाई तक ड्रोन उडाकर डेमो दिया।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908